

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

तहसील अधिकारी-नरेश कुमार शर्मा  
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 17/2010



राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी), दौसा

..प्रार्थी

बनाम

गीता देवी पत्नी जगदीश पुत्र श्रीनारायण जाति घोबी निवासी काली पहाडी तहसील दौसा  
..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)  
भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थिति-1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार  
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 07.08.2018

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967/16 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीया को किया गया। अप्रार्थीया द्वारा आवण्टन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 28.06.2002 को ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967/16 रकबा 0.25 है0 आवण्टित की गई थी। अप्रार्थी का आवंटन दिनांक से अपील/प्रा0 पत्र 14 (4) प्रस्तुत करने की दिनांक तक कब्जा नहीं रहा न ही आवंटित भूमि पर कब्जाकाशत की है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात की पेश की गई हैं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) की शर्तों की पालना नहीं की है। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि आवंटन नियमों के अनुसार जब से प्रार्थीया को भूमि खसरा नंबर 1967/16 रकबा 0.25 एयर का कब्जा सँभलाया है तब से काशत करती आ रही है। वर्तमान जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज है व प्रार्थीया द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर काशत कर रही है। हल्का पटवारी ने प्रार्थीया के खिलाफ दुर्भावना रखने वाले लोगों से मिलीभगत करके झूठी कार्यवाही की है, इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीया ने वरवक्त बहस अपने समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 पेश की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए आवंटन बहाल रखा जावे।



उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीया द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जाँच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीया को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को ग्राम काली पहाड़ी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन किया गया। तहसीलदार दौसा द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थीया के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 14 (4) पेश किया गया गया है। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई होना तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज होना व आवंटन हुए लगभग 16 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज होना अपने प्रा0 पत्र व वरवक्त बहस में बताया है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग व उपभोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते हैं। प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नामान्तरकरण की प्रति एवं खसरा गिरदावरी संवत 2063-2066 पेश की गई है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में आवंटित भूमि पडत बताई गई है। इससे यह तो कतई स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन भूमि का आवंटन के पश्चात कोई उपयोग नहीं किया गया। भू-आवंटन समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को आवंटन किया गया। आवंटन नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात का कब्जाकाश्त अथवा फसल किये जाने का प्रमाण पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीया द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2071-74 पेश की गई है, जो आवंटन के काफी समय बाद की है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी का आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त रहा है। आवंटन नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा होने की सूरत में ही गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आवंटी द्वारा इस प्रकरण में संवत 2071 से पूर्व के कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। प्रार्थीया द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु भी वरवक्त बहस आवेदन-पत्र पेश किया गया था किंतु ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्व-स्पष्ट है इसलिए प्रस्तुत प्रा0 पत्र में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीया द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीया के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 07 अगस्त, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा

